प्रेस नोट

9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफायनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स—एचपीसीएल एवं राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम में परियोजना के संचालन हेतु MOU

यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफायनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स का सिमश्रण है अर्थात् पहली बार दोनों एक साथ होने का प्रदेश में अनूठा प्रयास किया गया है।

- परियोजना लागत— रूपये 43,129 करोड
- Viablity Gap Funding (VGF)— रूपये 1123 करोड प्रतिवर्ष
- उत्पाद— Fuels and Petrochemicals
- Dept Equity Ratio- 2:1
- Equity Share HPCL 74%: GoR 26%
- परियोजना स्थलः पचपदरा, बाडमेर
- 4800 एकड राजकीय भूमि का आवंटन तथा इसकी कीमत का रूपये 200 करोड तक राज्य सरकार की Equity में गणना
- इन्दिरा गांधी नहर से 28 MGD पानी की उपलब्धता

राज्य सरकार को दीर्घ कालीन मिलने वाले लाभः

- राज्य हित में Project IRR को 15% से घटाकर 14% किया गया।
- परियोजना को राज्य सरकार से प्रदत्त Incentive (ब्याज मुक्त ऋण/वैट का आस्थगन) को रूपये 3736 करोड प्रतिवर्ष (15 वर्षों के लिये) से घटाकर रूपये 1123 करोड प्रतिवर्ष किया गया, जिससे राज्य सरकार पर पडने वाले वित्तीय भार में लगभग रूपये 40000 करोड की बचत की गई।
- पूर्ववर्ती सरकार के समय राज्य सरकार पर कुल वित्तीय भार रूपये 56040 करोड़ का था जो अब घट कर 16845 करोड़ रह गया है।
- Refiniry Configuration के चयन में 2.5 मिलियन टन वार्षिक राजस्थान कुड का Process करने की क्षमता होगी, जिसमें 1.5 मिलियन टन वार्षिक कुड से अधिक अर्थात 2.5 मिलियन टन वार्षिक राजस्थान कुड को Process बिना अतिरिक्त लागत के किया जायेगा।
- राज्य सरकार के Equity Share में रूपये 133 करोड़ से अधिक की कमी आई है अर्थात पूर्व में सहमत रूपये 3871 करोड़ के स्थान पर अब रूपये 3738 करोड़ लगेगें।

- वर्ष 2013 में राज्य सरकार को परियोजना में निवेश पर 6.2% का रिटर्न मिलना प्रस्तावित था, जो अब बढकर 12% हो गया है।
- PwC के अनुसार परियोजना अवधि 30 वर्षों के दौरान राज्य सरकार को मिलने वाली अतिरिक्त आय लगभग रूपये 34000 करोड आंकी गई है।

औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर:

- रिफायनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स की स्थापना से बाडमेर, जोधपुर एवं समीपवर्ती क्षेत्र में सहायक उद्योगों (Ancillary Industries) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे राज्य में औद्योगिकीकरण बढावा मिलेगा।
- परियोजना से पेट्रोल डीजल जैसे पेट्रोउत्पाद के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पेट्रोकेमिकल उत्पाद उत्सर्जित होगें, जिनमें पॉलीप्रोपिलिन, पॉली एथिलिन, बूटाडाईन, बेन्जिन, तउलीन एवं जाएलीन आदि प्रमुख है।
- रिफायनरी संचालन पर प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, किन्तु सहायक उद्योगों (Ancillary Industries) के लगने से अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें स्थानीय लोगों को प्रथमिकता दी जाएगी।
- 4 वर्षों की निर्माण अवधि में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कामगारों की अधिक आवश्यकता होगी।
- राज्य सरकार का प्रयास होगा कि रिफायनरी परिधि क्षेत्र में ग्रीन जोन एवं नवीन औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाए।

PRESS NOTE

9 MMTPA Refinery cum Petrochemical Complex – JV Project between HPCL & GoR

This project is integrated with Refinery & Petrochemical Complex, which is first of its kind in India.

Project Details

- Project Cost Rs 43,129 cr
- Debt Equity Ratio 2:1
- Equity Share HPCL 74% & GoR 26%
- VGF Rs 1123 cr interest free loan by GoR
- Products Fuels & Petochemicals
- Project Location Pachpadra, Barmer (4800 acre government land allotted by GoR &
- 28 MGD Water from IGNP allotted by GoR

Benefits to the State

- State's interest has been taken care of while finalizing the project at 14%
 Project IRR as against previously agreed 15%.
- Tax deferral/interest free loan of Rs 1123 cr per annum for 15 years instead of earlier agreed interest free loan of Rs 3637 cr per annum for 15 years. This has resulted in cost saving of about Rs 40,000 cr to the State exchequer over 15 years.
- Earlier financial burden on the State Government in terms of interest free loan was Rs 56,040 cr and now it has come down to Rs 16,845 cr in terms of tax deferral.
- 2.5 MMTPA Rajasthan crude shall be utilized till the project life. In case
 of non-availability of Rajasthan crude, it would be substituted by
 imported Arab Mix crude for the project life of the refinery without any
 cost enhancement.
- Equity share of GoR has been retained as 26% and GoR component has come down to Rs 3738 cr in comparison to previously agreed Rs 3871 cr.
- Previously State Government was getting only 6.2% return on investment. Now, State would be getting 12% return from this Project.

 Further, State would be getting additional income to the tune of Rs 34,000 cr over 30 years from the project only as per the estimates of PwC . However, indirect impact from downstream industries would be more.

Socio-Economic Impact of the Refinery-cum-Petrochemical Complex:

- The proposed Refinery has the potential to become an anchor industry for developing downstream and other service sector industries in and around the region.
- Due to its very nature, petrochemicals is an 'enabler' industry playing a vital role in the functioning of virtually all key sectors in the economy including packaging, agriculture, infrastructure, healthcare, textiles, automobile and consumer goods. Petrochemicals provide inputs which enable almost all other sectors to grow.
- With RRP, there shall be a Direct, Indirect and Induced economic impact on the economy of Rajasthan, which shall result in substantial increase in Output, Employment and Tax earnings in the State.
- This would provide opportunity of employment directly to the 1000 persons in refinery operation and would impact indirect employment to the thousands of people. Priority would be given to the local people.
- State will make the effort for the development of Green Zone and new industrial area in vicinity of Complex.